फ़ोटो: स्पार्क, मुंबई

शौचालय पास दिखाती हुई महिला

एक सराहनीय पहल

सामुदायिक शौचालय ब्लॉक

मरिया व इन्दू

स्पार्क **-** *(सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ़ एरिया रिसोर्स सेंटर्स)* मुंबई की एक गैर सरकारी संस्था है जो घरों, मोहल्लों और रोज़गार के अवसरों में सुधार लाने के लिए समुदायों के साथ काम करती है। *स्पार्क, राष्ट्रीय झोंपड़पट्टीवासी संगठन* और *महिला मिलन* के साथ गठबंधन के रूप में काम करती है। *राष्ट्रीय झोंपड़पट्टीवासी संगठन* एक समुदाय आधारित संस्था है जिसका गरीबों को विस्थापन के विरूद्ध संगठित करने, अपने मुद्दों को मुखरित करने और समस्याओं का हल ढूंढ़ने के साथ-साथ शहरी गरीबों के लिए पानी और स्वच्छता जैसी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने की ओर प्रयास करने का इतिहास है। *महिला मिलन* गरीब महिलाओं का एक विकेन्द्रित तंत्र है जहां महिलाएं अपने-अपने समुदायों में बचत और ऋण संबंधित गतिविधियां संभालती हैं। यह महिला गुटों के उस सामर्थ्य की पहचान करता है जिसके द्वारा वे समाज संबंधों में परिवर्तन लाकर गरीब परिवारों के जीवन में सुधार ला सकती हैं।

समुदाय लिंगभेद के प्रति संवेदनशीता

स्पार्क, राष्ट्रीय झोंपड़पट्टीवासी संगठन एवं *महिला मिलन* के गठबंधन का स्पष्ट केंन्द्र बिंदु है: गरीबों में सबसे गरीब और उनमें भी विशेष रूप से महिलाएं घर और समुदाय

संबंधित सभी मुद्दों के केन्द्र में तो हैं लेकिन उनका योगदान अधिकतर अप्रत्यक्ष व अनदेखा कर दिया जाता है। अर्थपूर्ण परिवर्तन तब होता है जब इस योगदान को प्रत्यक्ष बनाकर महिलाओं को और अधिक औपचारिक हस्तक्षेप में भाग लेने के लिए सामर्थ्य, समर्थन और संसाधन दिए जाएं। यदि यह जागरूकता से नहीं किया जाए तो महिलाएं अपनी भूमिका त्याग देती हैं और पुरुष नेतृत्व हासिल कर लेते हैं। महिलाओं को शामिल करना एक साधन भी है क्योंकि इसके द्वारा निरंतरता, व्यावहारिक समाधान और जन आंदोलनों में समानता का आश्वासन मिलता है। सामूहिक सहभागिता द्वारा हस्तक्षेप में महिलाओं की उपेक्षा करना कठिन है। यह उस परम्परागत समुदाय संगठन के विपरीत है जहां हस्तक्षेप युक्तियां एकल पुरुष नेता के इर्द-गिर्द बनती हैं।

शौच व्यवस्था

भारत में झोपड़पट्टी शौच व्यवस्था परम्परागत रूप में नगरपालिकाओं या अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा की जाती है और समुदाय की सहभागिता इसमें यदा-कदा ही हुई है। शौचालयों की जगह, उनके डिज़ाइन, भौतिक निर्माण की संस्थाओं और रखरखाव के मुद्दों पर नगरपालिका अधिकारी निर्णय लेते हैं और संबंधित समुदायों से कभी राय नहीं ली जाती। प्रक्रिया इंजीनियरों और ठेकेदारों द्वारा तय की जाती है और इनका रखरखाव नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी अपने कर्तव्यों से जी चुराने के लिए बदनाम है और नौकरशाही तंत्र इन्हें व्यवस्थित करने में असमर्थ है। इसके अलावा वे स्थानीय समुदायों के प्रति अनुग्रहित न होने के कारण उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होते। समुदाय की भी इस प्रक्रिया में कोई भागीदारी नहीं होती और इसलिए समुदाय अपने लिए बनायी गयी 'सम्पत्ति' के प्रति कोई स्वामित्व का भाव नहीं रखता।

परिणाम सबके सामने हैं— ये शौचालय एक या दो वर्षों में निष्क्रिय हो जाते हैं। अतः हमारे अधिकांश शहरों में बहुत कम चालू शौचालय हैं और लोगों को जबरन खुले में शौच करना पड़ता है। रेलवे पटरियों और शहरों के अन्य सार्वजनिक इलाकों में 'उघड़े पिछवाड़े' दिखना शहर का एक साधारण अनुभव हो गया है। महिलाओं को इस प्राकृतिक कार्य के लिए अंधेरा होने का इंतज़ार करना पड़ता है। बच्चे कहीं भी बैठ जाते हैं और मल सभी जगह फैल जाता है। इन अस्वच्छ परिस्थितियों और पर्यावरण जोखिमों के कारण गरीबों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।

इस स्थिति को सुधारने के लिए परोपकारी और अन्य संस्थाएं 'भुगतान और उपयोग' के शौचालयों का निर्माण करती हैं। यह व्यवस्था रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों आदि जैसे भीड़ वाले इलाकों में अच्छी चलती हैं। लेकिन झोपड़पट्टियों के लिए इसकी व्यावहारिकता में शक है क्योंकि शौचालय के प्रयोग का खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है— साधारणतया दो रुपये प्रति व्यक्ति प्रति उपयोग। सरकारी प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए शौचालय की तरह इन 'भुगतान और उपयोग' शौचालयों में समुदाय की भागीदारी का प्रश्न ही नहीं उठता।

महिला मिलन ने शौचालयों के गंदे होने के कारणों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि बड़े शौचालय काफी दूर-दूर थे और शौचालयों और घरों का अनुपात 1-4 से अधिक होने के कारण यह सेवा निराशजानक रूप से अपर्याप्त है। शौचालयों की व्यवस्था और रखरखाव उचित नहीं है। क्योंकि निर्माण में घटिया माल का इस्तेमाल किया गया था वे सदैव खराब और निष्क्रिय रहते थे। शौचालयों के लिए बच्चों और वयस्कों में होड़ होती थी और हमेशा बच्चों को भगा दिया जाता था। बच्चे बाहर ही बैठ जाते थे जिससे गंदगी फैलती थी। शौचालयों के डिज़ाइन बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थे।

नवनिर्मित शौचालय ब्लॉक

फ़ोटो: स्पार्क, मुंबई

विकल्प सुझाते समय महिलाएं बहुत स्पष्ट थीं कि उन्हें सामुदायिक शौचालय व्यवस्था चाहिए। इसके लिए उन्होंने कुछ कारण बताए— पहला, यदि व्यक्तिगत शौचालय बनाए जाएं तो प्रत्येक इकाई को मुख्य मलप्रवाह तंत्र से जोड़ने का खर्च काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। दूसरा, घर छोटे-छोटे होते है और पानी की आपूर्ति अपर्याप्त जिससे शौचालय साफ़ रखना कठिन है और रसोई के पास होने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं होने का डर है।

गठबंधन ने ब्लॉक शौचालय परियोजना निर्माण द्वारा न केवल बेहतर स्वच्छता प्राप्त करने बल्कि समुदाय को संगठित करने का भी प्रयास किया। समुदाय शौचालय ब्लॉकों का प्रारम्भ में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने विरोध किया जबकि व्यक्तिगत शौचालयों में कठिनाइयों की पहचान की जा चुकी थी। परन्तु महिला झोपड़पट्टीवासियों पर पुणे शौचालय परियोजना का प्रभाव काफी अच्छा रहा है।

1999-2000 में लगभग 3500 शौच सीटों के 220 शौचालय ब्लॉकों का गैर सरकारी संगठनों द्वारा निर्माण करने का निर्णय लिया गया। समाचार पत्रों में शौचालय निर्माण के लिए बोली लगाने के लिए गैर सरकारी संगठनों का आह्वाहन किया गया। उनसे अपेक्षा थी कि वे नगरपालिका द्वारा अनुमानित लागत से कम कीमत लगायेंगे। समुदाय और संगठन को यह गारंटी भी देनी थी कि अगले 30 वर्षों तक शौचालयों का रखरखाव समुदायिक योगदान द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए आठ गैर सरकारी संगठनों का चयन किया गया। इनमें से एक *स्पार्क* भी थी और *महिला मिलन* ने निर्माण करने का बीड़ा उठाया था।

पहली प्राथमिकता उन बस्तियों को दी गयी जहां कम से कम जनसंख्या 500 लोगों थी और जहां शौचालय सुविधाएं नहीं थीं। दूसरी प्राथमिकता में वे क्षेत्र थे जहां सुविधाएं मौजूद थीं पर इतनी जीर्ण-शीर्ण की उन्हें तोड़कर पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता थी। अंतिम प्राथमिकता उन झोपड़पट्टियों की थी जहां शौचालय थे पर पचास लोगों के लिए एक सीट के नियत अनुपात से कम थे।

काम की प्रगति का निरीक्षण और समस्याओं से निपटने के लिए नगरपालिका आयुक्त ने गैर सरकारी संगठन, समुदाय प्रतिनिधि और संबद्ध नगरपालिका कर्मियों के साथ प्रति सप्ताह मीटिंग की। इन मीटिंगों द्वारा *महिला मिलन* का आत्मविश्वास बढ़ा और जैसे-जैसे उन्हें काम का अनुभव हुआ वे अधिक भरोसे से चर्चाओं में भाग लेने लगीं।

पुणे में इस कार्यक्रम के दो चरणों में 2000 शौच सीटें और बच्चों की 500 से अधिक सीटों वाले कुल 114 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण किया गया है। इससे मिलता-जुलता कार्यक्रम बृहन्मुंबई नगरपालिका ने वर्ल्ड बैंक द्वारा फंड की गई *मुंबई सीवरेज परियोजना एक एवं ग्यारह* में चलाया जिसमें 5135 सीट वाले 251 शौचालयों का निर्माण किया गया। इसी प्रकार के प्रयोग वाइजैग और तिरपुर में किए गए हैं। इस तरह से निर्मित समुदाय शौचालय ब्लॉकों द्वारा कुल एक लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। इस काम ने भारत सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया है जिसके कारण एक राष्ट्रीय स्वच्छता नीति योजनाबद्व की गई है। इस नीति के तहत शहरी स्वच्छता योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

निष्कर्ष

इस कार्यक्रम में महिलाओं का सशक्त होना एक मिसाल है। परिवार और घर के निजी दायरे से चलकर मंडी और समुदाय तक की यात्रा इन अनपढ़ बस्तीवासी महिलाओं के लिए आसान नहीं है। हर स्तर पर नगरपालिका अधिकारियों के साथ बात-चीत और विचार-विमर्श ने इन महिलाओं को और अधिक सक्षम बनाया है। झोपड़पट्टी में रहने वाली महिलाओं के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को उत्तरदायी बनाने की प्रक्रिया भविष्य के लिए अच्छा चिन्ह है क्योंकि अच्छे प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है सत्ताधारियों का गरीबों के प्रति उत्तरदायी होना।

इसके अलावा गरीब कितने ही संगठित क्यों न हों, अपने लिए वे बाज़ार से या राज्य से आधारभूत सुविधाएं हासिल नहीं कर पाते। सफलता के लिए सभी पक्षधरों को पारस्परिक लाभदायक संबंध बनाकर एक साथ काम करना होगा। पुणे में यह एकजुटता देखने को मिली है जिससे अन्य शहर भी प्रेरणा ले सकते हैं।

साभारः स्पार्क, महिला मिलन, राष्ट्रीय झोपड़पट्टीवासी संगठन